द कल्टिवेटर

वर्ष-1, अंक-7 : मार्च 2025

जायका कृषि परियोजना-2 की मासिक ई-पत्रिका

THE CULTIVATOR

MONTHLY E-PAPER OF HPCDP (PHASE-II), JICA-ODA

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कृषि की 8 योजनाओं का ऐलान किया

वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में किसान व ग्रामीण हितों को दी विशेषता

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश की लगभग दो तिहाई जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी है। बेहतर प्रबन्धन के लिए सरकार द्वारा वर्तमान में चल रही आठ योजनाओं को मुख्यमन्त्री कृषि संवर्धन योजना एवं मुख्यमन्त्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के रूप में एकीकृत किया गया है। 2025-2026 के दौरान उक्त योजनाओं के अन्तर्गत 35 करोड़ रूपये व्यय किए जाने का प्रस्ताव है।

1. प्रदेश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तम्भ, किसानों के हित में सरकार 'एग्रीकल्चर लोन इंटरस्ट सबवेंशन स्कीम' लाएगी। जिसके तहत ऐसे किसानों जिनकी जमीन नीलामी की कगार पर आ गई हो, उनके द्वारा लिए गए 3 लाख रूपये कृषि लोन को चुकाने हेतु, सरकार बैंकों के माध्यम से वन टाईम सैटलमेंट पॉलिसी लाएगी। इस पॉलिसी के अन्तर्गत मूल धन पर लगने वाले ब्याज का 50 प्रतिशत हिस्से का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत 50 करोड़ रूपये व्यय किए जाएंगे।

2. 2025-2026 के दौरान एक लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है। प्राकृतिक खेती करने वाले सभी किसानों को हिम परिवार रजिस्टर से जोड़ा जाएगा तथा साथ ही सर्टिफिकेशन के लिए नए किसानों को 'सर्टिफाईड इवेल्युएशन टूल फॉर एग्रीकल्चर रिसोर्स एनालीसिस' (सेंटरा पोर्टल) पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा।

3. राज्य में प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए मक्का पर भारत में सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया है। वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए मक्का के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 से बढ़ाकर 40 तथा गेहूं को 40 से बढ़ाकर 60 रूपये प्रति किलो किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई किसान 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित नोटिफाइड कोलेक्शन सेंटर पर स्वयं ले कर आते हैं तो उन्हें 2 रुपए प्रति किलो की दर से फ्राइट सब्सिडि भी दी जाएगी। किसानों को बेहतर मार्केटिंग के माध्यम से बेहतर मूल्य हेतु ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एनसीडीसी (नेशल कॉपरेटिव डिव्लपमेंट कॉर्पोरेशन) से भी जोड़ा जाएगा।

4. विश्व में 78 प्रतिशत् हल्दी उत्पादन के साथ भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। भारत में पैदा होने वाली हल्दी अपने हाई क्युरकमिन कंटेंट के लिए प्रसिद्ध है। अत: प्रदेश के पास प्राकृतिक हल्दी के रूप में उत्पादन में आगे बढ़ने का एक सुनहरा अवसर है। इस सन्दर्भ में निम्न दो घोषणाएं की गई।

(क) जिला हमीरपुर में स्पाईस पार्क का निर्माण किया जाएगा। इससे प्रदेश में उगाए जा रहे मसालों की वैल्यू एडिशन होगी व बाजार में एक नई पहचान मिलेगी।

(ख) आगामी वित्त वर्ष से प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए कच्ची हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 90 रूपये प्रति किलो करने की घोषणा की गई।

5. 2025-2026 के दौरान कृषि विभाग के सभी गवर्नमेंट फार्मस को प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत लाया जाएगा और किसानों को इन फार्मस का और अधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से निम्न कदम उठाए जाएंगे।

(क) 15-20 प्रतिशत हिस्से में पारम्परिक फसलों (हल्दी, अदरक, अरबी, कटहल, रतालू आदि) की खेती की जाएगी और विभिन्न प्रकार की फसलों हेतु पांच नए मॉडल फार्म विकसित किए जाएंगे।

(ख) आईसीएआर-सीपीआरआई द्वारा विकसित एसओपी के तहत खरीफ 2025 से आलू के बीज का उत्पादन आठ पोटेटो डिव्लपमेंट स्टेशन में फिर से शुरू किया जाएगा।

6. प्रदेश की कृषि क्षेत्र में वर्षों से आलू एक महत्वपूर्ण फसल है। राज्य में कुल सब्जी उत्पादन में आलू का 20 प्रतिशत हिस्सा है। अत: आलू की फसल को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ऊना जिले में लगभग 20 करोड़ रूपये की लागत से 500 केजी पर ऑवर की क्षमता वाले पोटेटो प्रोसिंग प्लांट को स्थापित करने जा रही है। जोकि प्रदेश में वर्ष के दौरान 3 हजार 400 हैक्टेयर में उगने वाली आलू की दोनों मौसमों की फसलों के लगभग 54 हजार 200 मीट्रिक टन आलू उत्पादन करने वाले किसानों को सहायता प्रदान करने में सहायक होगा।

7. गेहूँ और मक्का के बेहतर भण्डारण के लिए प्रदेश में उच्च तकनीक से चालित सायलस स्थापित किये जाएंगे।

8. सरकार प्रदेश के किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं और 'हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना' इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आगामी वित्त वर्ष में सरकार इस परियोजना हेतु 154 करोड़ रुपये का व्यय करेगी। परियोजना के तहत निम्न महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे।

(क) 100 गाँवों में सिंचाई योजनाओं का निर्माण करके उन्हें लोकल कमेटी को ट्रांसफर किया जाएगा।

(ख) कृषि यन्त्रीकरण पर सहायता प्रदान करने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

(ग) परियोजना क्षेत्र के लाभार्थी किसानों के लिए 1 हजार 500 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे व लगभग 4 हजार डेमोस्ट्रेशन ऑन वेजिटेबल कल्टीवेशन आयोजित की जाएंगी।

(घ) मिलेट्स के प्रचार-प्रसार के साथ खाद्यान्न उत्पादकता पर लगभग 2 हजार 400 डेमोस्ट्रेशन आयोजित की जाएंगी।

9. 'मुख्यमन्त्री खेत संरक्षण योजना' को आगे बढ़ाते हुए अब किसानों को जंगली जानवरों से फसलों की रक्षा हेतु सोलर फैंसिंग जाली दार और कान्टेदार बाड़बंदी में सहायता प्रदान की जाएगी।

कृषि उपज मण्डीकरण के प्रयास तेज करें : डॉ. सुनील चौहान

मण्डी। जायका कृषि परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान ने परियोजना जिला इकाई मण्डी के अधिकारियों को निर्देश दिये कि फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्षेत्र विशेष में उगाई जाने वाली व्यावसायिक फसलों की पहचान करें और जायका वेजिटेबल गार्डन व फ्लैगशिप फसलों का पूरा ब्यौरा निरंतर बनाना जारी रखें। डॉ. सुनील चौहान मंगलवार को जिला परियोजना प्रबंधन, इकाई, मंडी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जायका किचन गार्डन में पूरा साल फसलें लगाने का पूरा ब्यौरा बनाकर उसे लागू करवाने के निर्देश भी दिए। डॉ. चौहान ने कहा कि फसल विविधीकरण के साथ-साथ किसानों को कृषि व्यापार संस्थाओं से जोड़ना भी जरुरी है ताकि उन्हें कृषि उत्पादों को उचित व अधिक मूल्य मिल सके।

इस बैठक में राज्य परियोजना प्रबंधन की ओर से उप परियोजना निदेशक डॉ. राजेश कुमार, डॉ. दुर्गा दत्त शर्मा, पीएमसी से डॉ. आरएस ठाकुर, जिला परियोजना अधिकारी डॉ. हेम राज वर्मा और परियोजना से जुड़े अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

इसी बीच अधिकारियों ने गधिमण मझोटी और सुरथी थाची सिंचाई परियोजनाओं का दौरा किया। इन सिंचाई उप-परियोजनाओं में उगाई जा रही मटर की फसल को देखा और कुछ प्रगतिशील किसानों के साथ भेंट की तथा उनसे सीआईसी और एफपीओ के गठन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने यह निर्देश दिए कि गोहर क्षेत्र मटर की खेती के लिए उपयुक्त है और किसानों को एकत्रित हो कर खेती और मार्केटिंग के बारे में सोचना चाहिए जिससे सभी किसान ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हों।

डॉ. पॉलरासु ने मोटे पोषक अनाजों को लोकप्रिय बनाने का आह्वान किया

हमीरपुर, 29 मार्च। हिमाचल प्रदेश के कृषि सचिव डॉ. सी. पॉलरासु ने किसानों को पोषक मोटे जनाजों के महत्व के बारे में बताया, किसानों की सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार की ओर से आश्वासन दिया। डॉ. पॉलरासु शनिवार 29 मार्च को सुंदरनगर में मोटे पोषक अनाज के मेले और प्रदर्शनी के अवसर पर बोल रहे थे। डॉ. सी. पॉलरासु इस योजना में मुख्य अतिथि थे।

कृषि सचिव ने बताया कि सरकार प्राकृतिक खेती से उगाई गेंहू 60 रु. प्रति किलो, मक्का 40 रु. प्रति किलो और हल्दी 90 रु. प्रति किलो की दर से खरीदेगी। उन्होंने इस मौके पर मोटे पोषक अनाजों को उत्पादन कर रहे 25 प्रगतिशील किसानों को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में मंडी जिले के पोषक तत्व उत्पादक उत्पादक 584 किसानों ने भाग लिया।

डॉ. पॉलरासु ने आयकर कृषि प्रतियोगिता की ओर से बनाई गई प्रदर्शनी भी देखी, जिसमें मोटे पोषक अनाज के उत्पादक कृषक समूहों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में सुदंरनगर में जायका की सहायता से बने पारंपरिक फूड कोर्ट की नेत्री रक्षा देवी को भी कृषि सचिव ने सम्मानित किया। इस मोटे पोषक अनाज मेले व प्रदर्शनी में जायका कृषि परियोजना की ओर से परियोजना उपनिदेशक डॉ. डीडी शर्मा, परियोजना जिला मंडी के परियोजना प्रबंधक डॉ. एचआर वर्मा ने परियोजना में खरीफ 2024 के दौरन लगाए गए प्रदर्शन की जानकनी दी।

उल्लेखनीय है कि जायका कृषि परियोजना ने राज्य की नीति के अनुसार मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए खरीफ-2024 के दौरान 42.03 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती के लिए फिंगर मिलेट के 45 प्रदर्शन भी लगाए। परियोजना ने राष्ट्रीय बीज निगम से फिंगर मिलेट का 8.60 क्विंटल प्रमाणित बीज प्राप्त किया। परिणामस्वरूप 188.86 क्विंटल मोटे अनाज का उत्पादन हुआ। परियोजना क्षेत्र में यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

इस अवसर पर पद्मश्री नेक राम शर्मा हिमाचल प्रदेश, संयुक्त निदेशक कृषि (उत्तरी क्षेत्र) धर्मशाला डॉ. राहुल कटोच उपमंडलीय अधिकारी अमर नेगी, किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष सीता राम वर्मा ने किसानों की समस्याएं उठाई। संयुक्त निदेशक कृषि (उत्तरी क्षेत्र) धर्मशाला डॉ. राहुल कटोच ने किसानों को पोषक अनाजों और उनसे संबंधित उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित किया। कृषक प्रशिक्षण केंद्र सुंदरनगर की प्रिंसिपल डॉ. प्राची ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। किसानों सहित का स्वागत किया। कार्यक्रम का आरंभ मिलेट गीत और मिलेट प्रतिज्ञा के साथ हुआ। कृषि विज्ञान केंद्र मंडी स्थित सुंदरनगर के वैज्ञानिकों ने पोषक अनाज उगाने व इनके मूल्यसंवर्धन के बारे में किसानों को विस्तृत आनकारी दी।

इस अवसर पर कृषि विभाग, आत्मा परियोजना, कृषि विज्ञान

बरान बिहाल सेरी सिंचाई उप परियोजना किसानों को सौंपी

कुल्लू। हिमाचल प्रदेश में चल रहे फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 के तहत खण्ड परियोजना प्रबंधन इकाई, कुल्लू, जिला कुल्लू के द्वारा तहसील मनाली के गाँव बरान में बनाई गई, बहाव सिंचाई परियोजना बरान-बिहाल-सेरी का निर्माण कार्य पूरा होने के उपरान्त दिनांक 21 मार्च, 2025 को कृषक विकास संगठन बरान को सौंपी गई।

जायका के तहत बनी इस सिंचाई उप परियोजना के निर्माण कार्य में 48,42,682/- रुपये खर्च किए गए। इस सिंचाई परियोजना के बनने से लगभग 24.55 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा और 108 किसान परिवार लाभान्वित होंगे।

इस मौके पर परियोजना प्रबंधक मंडी डॉ. हेम राज वर्मा ने सभी लाभान्वित किसानों को

इस सिंचाई परियोजना के पूरा होने की बधाई देते हुए कहा कि जायका परियोजना का मुख्य लक्ष्य फसल विविधीकरण करके किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है।

कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी होने के कारण किसान फसलों की सही पैदावार नहीं ले पाते थे, जायका के तहत ऐसे क्षेत्रों में पहले सिंचाई उप परियोजना को स्थापित करके कुहल आदि का निर्माण करवाया जाता है जिससे सभी किसान नगदी फसलों का उत्पादन करके फसलों के अच्छे दाम ले सकें और अपनी आर्थिक में सुधार ला सकें।

इस उपलक्ष्य पर ग्राम पंचायत प्रधान धनी देवी कृषक विकास संगठन बरान से उप-प्रधान पुने राम, सचिव अमित भण्डारी, कृष्णा देवी व अन्य गांव के किसान और खण्ड परियोजना प्रबंधन इकाई कुल्लू से खण्ड परियोजना प्रबंधक डॉ. गोपाल चंद भारद्वाज, निर्माण अभियंता भरत भूषण और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

सोलन व मण्डी में एफपीओ बनाने के लिए कृषि उद्यमियों से विचार विर्मश

सोलन/मण्डी। जिला परियोजना प्रबंधन इकाई सोलन और मण्डी में शक्तिशाली विपणन लिंक के साथ बड़े पैमाने पर फसल विविधीकरण के लिए धरातल पर प्रणाली विकसित करने की प्रक्रिया शुरु हुई। परियोजना निदेशक के निर्देश पर जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, सोलन और मण्डी ने एक क्षेत्रीय कृषि व्यवसाय उद्यम के प्रमोटरों और प्रबंधकों की उपस्थिति की मेजबानी की, ताकि कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप (सीआईजी) के साथ बाजार संबंधों का पता लगाया जा सके और एमओडी के अनुसार किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया जा सके। टीम ने कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप की स्थिति जानने के लिए सोलन के निकट बरठीं में 19 मार्च को बासनी गांव का भी दौरा किया। इन दोनों

बैठकों में और गांवों के दौरों में परियोजना के वरिष्ठ सलाहकार बीएस संधू भी उपस्थित रहे। सोलन की मासिक समीक्षा बैठक 18 मार्च को परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान के संदेश के साथ आयोजित की गई, जिन्होंने इसके साथ ही कृषि व्यवसाय संबंधों के निर्माण पर भी चर्चा की गई। बैठक में एसपीएमयू के उप परियोजना निदेशक डॉ. राजेश कुमार, डॉ. डीडी शर्मा और डॉ. करतार डोगरा ने बैठक का संचालन और मार्गदर्शन किया और डॉ. आरएस ठाकुर कृषि विशेषज्ञ और सुशील कुमार शर्मा आईईसी विशेषज्ञ भी मौजूद थे। सोलन के खंड परियोजना प्रबंधक डॉ. अरुण शर्मा और किन्नौर के डॉ. प्रवीण अत्री तथा नाहन बीपीएमयू के प्रतिनिधियों ने कृषि व्यवसाय उद्यम के प्रतिनिधियों नवजोत सिंह सहोता, दुर्गा प्रसाद और विजय कुमार के साथ बातचीत करते हुए मासिक रिपोर्ट का ब्यौरा दिया।

सोलन के बाद, जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, मण्डी ने गोहर और बल्ह क्षेत्र में एक कृषि व्यवसाय उद्यम के प्रमोटरों और प्रबंधकों की उपस्थिति की मेजबानी की, जिसका मुख्य उद्देश्य कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप (सीआईजी) के साथ बाजार संबंधों का पता लगाना और एमओडी के अनुसार किसान उत्पादक संगठनों का गठन करना है। अधिकारियों और किसानों ने कृषि व्यवसाय उद्यम के प्रतिनिधियों नवजोत सिंह सहोता, विजय कुमार और दुर्गा प्रसाद उपाध्याय के साथ बातचीत करते हुए क्षेत्र में उत्पादित फसलें जैसे मटर और टमाटर का ब्यौरा दिया। टीम ने कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप की स्थिति जानने के लिए गोहर के गधीमन और बल्ह में ढाबण गांव के किसानों और कृषि उद्यमी से बातचीत की तथा कृषि में आने वाली समस्याओं और मार्केटिंग संबंधी मुद्दों पर विस्तृत

चर्चा की। बैठक में एसपीएमयू के उप परियोजना निदेशक डॉ. राजेश कुमार, डॉ. डीडी शर्मा और डॉ. करतार डोगरा ने बैठक का संचालन और मार्गदर्शन किया। मण्डी के जिला परियोजना प्रबंधक डॉ. हेम राज वर्मा, खंड परियोजना प्रबंधक, मण्डी और गोहर, मार्केटिंग ऑफिसर डीपीएमयू मण्डी तथा बीपीएमयू के प्रसार अधिकारी मौके पर मौजूद थे।

अधिकारियों और किसानों ने कृषि व्यवसाय उद्यम के प्रतिनिधियों नवजोत सिंह सहोता, विजय कुमार और दुर्गा प्रसाद उपाध्याय के साथ बातचीत करते हुए क्षेत्र में उत्पादित फसलें जैसे मटर और टमाटर का ब्यौरा दिया। टीम ने कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप की स्थिति जानने के लिए गोहर के गधीमन और बल्ह में ढाबण गांव के किसानों और कृषि उद्यमी से बातचीत की तथा कृषि में आने वाली समस्याओं और मार्केटिंग संबंधी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।

जायका कृषि परियोजना की कुछ मॉडल उप परियोजनाएं एक नजर में

एफआईएस बरजोहरू कोट ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई, गोहर

1. सिंचाई उप परियोजना का नाम	एफआईएस बरजोहरू कोट
2. अनुमानित लागत (रु.)	46,12,500/-
3. जी.सी.ए. (हेक्टेयर)	25.44
4. सी.सी.ए. (हेक्टेयर)	17.23
5. लाभार्थी किसान परिवारों की संख्या	66
6. जिला परियोजना प्रबंधन, इकाई	मंडी
7. ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई	गोहर
8. ग्राम पंचायत, तहसील, जिला	नाऊन, तहसील चच्योट जिला मंडी

उठाऊ सिंचाई उप परियोजना कसारला ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई, मंडी

1. सिंचाई उप परियोजना का नाम	कसारला
2. अनुमानित लागत (रु.)	1,26,58,600/-
3. जी.सी.ए. (हेक्टेयर)	44.12
4. सी.सी.ए. (हेक्टेयर)	37.38
5. लाभार्थी किसान परिवारों की संख्या	192
6. जिला परियोजना प्रबंधन, इकाई	मंडी
7. ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई	मंडी
8. ग्राम पंचायत, तहसील, जिला	कसारला, तहसील बल्ह, जिला मंडी

एलआईएस बसोल ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई, हमीरपुर

1. सिंचाई उप परियोजना का नाम	बसोल
2. अनुमानित लागत (रु.)	54,36,000/-
3. जी.सी.ए. (हेक्टेयर)	15.12
4. सी.सी.ए. (हेक्टेयर)	12.91
5. लाभार्थी किसान परिवारों की संख्या	31
6. जिला परियोजना प्रबंधन, इकाई	हमीरपुर
7. ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई	हमीरपुर
8. ग्राम, तहसील, जिला	रैल, जिला हमीरपुर

एफआईएस गधिमण मझोठी ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई, गोहर

1. सिंचाई उप परियोजना का नाम	गधिमण मझोठी
2. अनुमानित लागत (रु.)	44,55,000/-
3. जी.सी.ए. (हेक्टेयर)	25.21
4. सी.सी.ए. (हेक्टेयर)	14.91
5. लाभार्थी किसान परिवारों की संख्या	73
6. जिला परियोजना प्रबंधन, इकाई	मंडी
7. ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई	गोहर
8. ग्राम पंचायत, तहसील, जिला	मझोठी, तहसील चच्योट, जिला मंडी

एफआईएस बजगार खड़ से भरयारा, धथरी ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई, सरकाघाट

1. सिंचाई उप परियोजना का नाम	बजगार खड़ से भरयारा, धथरी
2. अनुमानित लागत (रु.)	1,61,58,800/-
3. जी.सी.ए. (हेक्टेयर)	88.04
4. सी.सी.ए. (हेक्टेयर)	62.17
5. लाभार्थी किसान परिवारों की संख्या	162
6. जिला परियोजना प्रबंधन, इकाई	मंडी
7. ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई	सरकाघाट
8. ग्राम पंचायत, तहसील, जिला	लधरूही, तहसील जोगिंदरनगर, जिला मंडी

टीडब्ल्यूआईएस ख्वाजा ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई, ऊना

1. सिंचाई उप परियोजना का नाम	टीडब्ल्यूआईएस ख्वाजा
2. अनुमानित लागत (रु.)	68,65,000/-
3. जी.सी.ए. (हेक्टेयर)	18.71
4. सी.सी.ए. (हेक्टेयर)	17.73
5. लाभार्थी किसान परिवारों की संख्या	80
6. जिला परियोजना प्रबंधन, इकाई	हमीरपुर
7. ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई	ऊना
8. ग्राम, जिला	ऊपर बेसल, जिला ऊना

एफआईएस फलतनाला ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई, कुल्लू

1. सिंचाई उप परियोजना का नाम	फलतनाला
2. अनुमानित लागत (रु.)	82,07,300/-
3. जी.सी.ए. (हेक्टेयर)	39.82
4. सी.सी.ए. (हेक्टेयर)	37.15
5. लाभार्थी किसान परिवारों की संख्या	92
6. जिला परियोजना प्रबंधन, इकाई	मंडी
7. ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई	कुल्लू
8. ग्राम पंचायत, तहसील, जिला	हाट, तहसील भुंतर, जिला कुल्लू

एफआईएस दोहग ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई, सरकाघाट

1. सिंचाई उप परियोजना का नाम	दोहग
2. अनुमानित लागत (रु.)	39,72,000/-
3. जी.सी.ए. (हेक्टेयर)	17.97
4. सी.सी.ए. (हेक्टेयर)	12.73
5. लाभार्थी किसान परिवारों की संख्या	61
6. जिला परियोजना प्रबंधन, इकाई	मंडी
7. ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई	सरकाघाट
8. ग्राम पंचायत, तहसील, जिला	ढेलू, तहसील जोगिंदरनगर, जिला मंडी

एफआईएस दुल्ला ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई, चंबा

1. सिंचाई उप परियोजना का नाम	एफआईएस दुल्ला
2. अनुमानित लागत (रु.)	18,80,600/-
3. जी.सी.ए. (हेक्टेयर)	9.30
4. सी.सी.ए. (हेक्टेयर)	8.79
5. लाभार्थी किसान परिवारों की संख्या	59
6. जिला परियोजना प्रबंधन, इकाई	पालमपुर
7. ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई	चंबा
8. ग्राम, तहसील, जिला	दुल्ला, तहसील चंबा, जिला चंबा

एफआईएस थारस ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई, कुल्लू

1. सिंचाई उप परियोजना का नाम	थारस
2. अनुमानित लागत (रु.)	92,35400/-
3. जी.सी.ए. (हेक्टेयर)	36.83
4. सी.सी.ए. (हेक्टेयर)	35.57
5. लाभार्थी किसान परिवारों की संख्या	116
6. जिला परियोजना प्रबंधन, इकाई	मंडी
7. ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई	कुल्लू
8. ग्राम पंचायत, तहसील, जिला	सड़ांध-द्वितीय, तह. भुंतर, जिला कुल्लू

एलआईएस माकडी ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई, बिलासपुर

1. सिंचाई उप परियोजना का नाम	एलआईएस, माकडी
2. अनुमानित लागत (रु.)	86,34,000/-
3. जी.सी.ए. (हेक्टेयर)	33.38
4. सी.सी.ए. (हेक्टेयर)	29.23
5. लाभार्थी किसान परिवारों की संख्या	118
6. जिला परियोजना प्रबंधन, इकाई	हमीरपुर
7. ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई	बिलासपुर
8. ग्राम, तहसील, जिला	माकडी, जिला बिलासपुर

एफआईएस मेरु ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई, चंबा

1. सिंचाई उप परियोजना का नाम	एफआईएस मेरु
2. अनुमानित लागत (रु.)	33,13,437/-
3. जी.सी.ए. (हेक्टेयर)	17.38
4. सी.सी.ए. (हेक्टेयर)	10.70
5. लाभार्थी किसान परिवारों की संख्या	34
6. जिला परियोजना प्रबंधन, इकाई	पालमपुर
7. ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई	चंबा
8. ग्राम, तहसील, जिला	मेरु, तहसील सलूणी, जिला चंबा

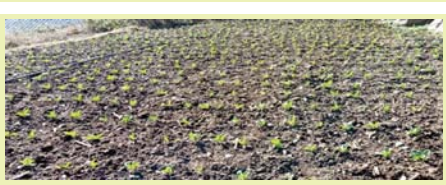

एफआईएस पाधर से आरंग ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई, मंडी

1. सिंचाई उप परियोजना का नाम	पाधर से आरंग
2. अनुमानित लागत (रु.)	51,66,000/-
3. जी.सी.ए. (हेक्टेयर)	24.70
4. सी.सी.ए. (हेक्टेयर)	13.63
5. लाभार्थी किसान परिवारों की संख्या	47
6. जिला परियोजना प्रबंधन, इकाई	मंडी
7. ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई	मंडी
8. ग्राम पंचायत, तहसील, जिला	सांवेर, तहसील पधर, जिला मंडी

एलआईएस छ्कोह ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई, बिलासपुर

1. सिंचाई उप परियोजना का नाम	छ्कोह
2. अनुमानित लागत (रु.)	79,60,000/-
3. जी.सी.ए. (हेक्टेयर)	25.04
4. सी.सी.ए. (हेक्टेयर)	17.55
5. लाभार्थी किसान परिवारों की संख्या	119
6. जिला परियोजना प्रबंधन, इकाई	हमीरपुर
7. ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई	बिलासपुर
8. ग्राम, तहसील, जिला	छ्कोह, जिला बिलासपुर

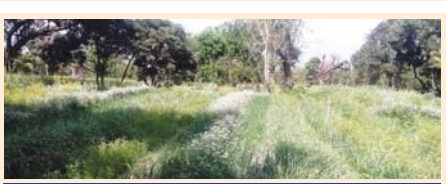

एफआईएस चनौर ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई, देहरा

1. सिंचाई उप परियोजना का नाम	एफआईएस चनौर
2. अनुमानित लागत (रु.)	61,93,400/-
3. जी.सी.ए. (हेक्टेयर)	85.39
4. सी.सी.ए. (हेक्टेयर)	68.50
5. लाभार्थी किसान परिवारों की संख्या	117
6. जिला परियोजना प्रबंधन, इकाई	पालमपुर
7. ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई	देहरा
8. ग्राम, तहसील, जिला	बेहेड और चनौर, तहसील डाडा शिबा, जिला कांगड़ा

जायका कृषि परियोजना की कुछ मॉडल उप परियोजनाएं एक नजर में

आठ नई योजनाओं से युक्त किसान हितकारी बजट 2025-26

हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने किसानों के लिए आठ नई योजनाओं की घोषणाएं करके बजट को किसानों के लिए हितकारी बजट बना दिया। साथ ही उन्होंने फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 के अंतर्गत वर्ष 2025-26 लक्ष्यों का भी ऐलान करके हमें प्रोत्साहित किया। किसानों के इस हितकारी बजट के भाषण के अंश हम परियोजना की ई-पत्रिका और अन्य संचार माध्यमों के जरिए गांवों तक पहुंचा कर अपनी जिम्मेदार भूमिका निभाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

इसी बीच जायका कृषि परियोजना ने सभी 15 खंड प्रबंधन इकाइयों में एक-एक मॉडल उप परियोजना विकसित करने का फैसला लिया है। इस तरह से 15 मॉडल उप परियोजना स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। इस कार्य को परियोजना के जमीनीस्तर के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने बहुत गंभीरता से लिया और इसकी प्रगति देखते हुए हमने 15 मॉडल उप परियोजनाओं की जगह 28 मॉडल उप परियोजनाएं बनाने का बेड़ा उठाया है जिसके लिए परियोजना का स्टाफ प्रशंसा का हकदार है।

सभी मॉडल उप परियोजना इस तरह से विकसित की जा रही है जिसमें परियोजना की सभी गतिविधियों लागू की जा सके। इन सभी मॉडल उप

परियोजनाओं में बाड़ लगाना, फार्म एक्सेस रोड बनाना, सब्जी बीज प्रदर्शन लगाना, जायका किचन गार्डन, जायका सब्जी गार्डन, शैप और पीएमवीआरपी से जुड़े कार्य शामिल हैं। शैप यानी छोटे किसानों के लिए बागवानी उत्पादन की राह बनाकर उन्हें बाजार से जोड़ने की अवधारणा है। पीएमवीआरपी के अंतर्गत फलैगशिप सब्जी या सब्जियों की पहचान कर उनका वाणिज्यिक उत्पादन करवाना। साथ ही एक रूचि रखने वाले किसान समूह बनाकर उनके लिए कृषि मंडीकरण के संपर्क बनाना व कृषि व्यापार से संबद्ध संगठनों से जोड़ना शामिल है।

इन मॉडल उप परियोजनाओं में विभिन्न परियोजना हस्तक्षेपों का विवरण दर्शाने वाले साइन बोर्ड भी लगाए जाएंगे। सभी जिला व खंड स्तर के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मॉडल उप परियोजना के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा बिंदु, बुनियादी ढांचे पर निर्धारित रंग व पैटर्न, पढ़े जाने वाले नारे, सब्जियों और खाद्यान्नों के प्रदर्शन सहित डिस्प्ले बोर्ड और अन्य हस्तक्षेपों को अनुक्रमणबद्ध संसूचित किया जाए।

ई-पत्रिका के इस अंक में सामग्री व छाया चित्रों के योगदान के लिए परियोजना का स्टाफ बधाई का पात्र है।

डॉ. सुनील चौहान
परियोजना निदेशक
एवं प्रधान सम्पादक

एफआईएस भगलाहर ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई, जवाली

1. सिंचाई उप परियोजना का नाम	एफआईएस भगलाहर
2. अनुमानित लागत (रु.)	77,74,300/-
3. जी.सी.ए. (हेक्टेयर)	79.37
4. सी.सी.ए. (हेक्टेयर)	76.13
5. लाभार्थी किसान परिवारों की संख्या	136
6. जिला परियोजना प्रबंधन, इकाई	पालमपुर
7. ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई	जवाली
8. ग्राम, तहसील, जिला	भगलाहर, तहसील जवाली, जिला कांगड़ा

एलआईएस सैमून-2 ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई, जवाली

1. सिंचाई उप परियोजना का नाम	एफआईएस भगलाहर
2. अनुमानित लागत (रु.)	87,10, 400/-
3. जी.सी.ए. (हेक्टेयर)	32.42
4. सी.सी.ए. (हेक्टेयर)	18.49
5. लाभार्थी किसान परिवारों की संख्या	50
6. जिला परियोजना प्रबंधन, इकाई	पालमपुर
7. ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई	जवाली
8. ग्राम, तहसील, जिला	समून, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा

एफआईएस मालती ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई, देहरा

1. सिंचाई उप परियोजना का नाम	एफआईएस मालती
2. अनुमानित लागत (रु.)	79,50,000/-
3. जी.सी.ए. (हेक्टेयर)	87.56
4. सी.सी.ए. (हेक्टेयर)	62.17
5. लाभार्थी किसान परिवारों की संख्या	335
6. जिला परियोजना प्रबंधन, इकाई	पालमपुर
7. ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई	देहरा
8. ग्राम, तहसील, जिला	नंदेहर तह. कांगड़ा, जिला कांगड़ा

एफआईएस वैदां दी कूहल ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई, पालमपुर

1. सिंचाई उप परियोजना का नाम	एफआईएस वैदां दी कुहल
2. अनुमानित लागत (रु.)	1,09,90,000/-
3. जी.सी.ए. (हेक्टेयर)	32.17
4. सी.सी.ए. (हेक्टेयर)	25.58
5. लाभार्थी किसान परिवारों की संख्या	123
6. जिला परियोजना प्रबंधन, इकाई	पालमपुर
7. ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई	पालमपुर
8. ग्राम, तहसील, जिला	रायपुर, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा

एफआईएस नन्रैया कूहल ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई, धर्मशाला

1. सिंचाई उप परियोजना का नाम	एफआईएस नन्रैया कुहल
2. अनुमानित लागत (रु.)	72,93,000/-
3. जी.सी.ए. (हेक्टेयर)	29.17
4. सी.सी.ए. (हेक्टेयर)	24.60
5. लाभार्थी किसान परिवारों की संख्या	268
6. जिला परियोजना प्रबंधन, इकाई	पालमपुर
7. ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई	धर्मशाला
8. ग्राम, तहसील, जिला	नन्रैया तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

एफआईएस छू नाला कूहल ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई, पालमपुर

1. सिंचाई उप परियोजना का नाम	एफआईएस छू नाला कूहल
2. अनुमानित लागत (रु.)	80, 97, 000/-
3. जी.सी.ए. (हेक्टेयर)	38.41
4. सी.सी.ए. (हेक्टेयर)	32.45
5. लाभार्थी किसान परिवारों की संख्या	91
6. जिला परियोजना प्रबंधन, इकाई	पालमपुर
7. ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई	पालमपुर
8. ग्राम, तहसील, जिला	सगुर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा

एफआईएस नयी कूहल ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई, धर्मशाला

1. सिंचाई उप परियोजना का नाम	एफआईएस नयी कूहल
2. अनुमानित लागत (रु.)	1, 79, 27, 600/-
3. जी.सी.ए. (हेक्टेयर)	56.29
4. सी.सी.ए. (हेक्टेयर)	51.40
5. लाभार्थी किसान परिवारों की संख्या	293
6. जिला परियोजना प्रबंधन, इकाई	पालमपुर
7. ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई	धर्मशाला
8. ग्राम, तहसील, जिला	पुहारा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा

एफआईएस ध्यारी ढली जदारी ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई, सोलन

1. सिंचाई उप परियोजना का नाम	ध्यारी ढली जदारी
2. अनुमानित लागत (रु.)	62,28,500/-
3. जी.सी.ए. (हेक्टेयर)	27.12
4. सी.सी.ए. (हेक्टेयर)	20.12
5. लाभार्थी किसान परिवारों की संख्या	82
6. जिला परियोजना प्रबंधन, इकाई	सोलन
7. ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई	सोलन
8. ग्राम, तहसील, जिला	श्रीनगर, जिला सोलन

एफआईएस रेडू खड़ से मनलोग ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई, सोलन

1. सिंचाई उप परियोजना का नाम	रेडू खड़ से मनलोग
2. अनुमानित लागत (रु.)	72,72,200/-
3. जी.सी.ए. (हेक्टेयर)	42.52
4. सी.सी.ए. (हेक्टेयर)	33.35
5. लाभार्थी किसान परिवारों की संख्या	74
6. जिला परियोजना प्रबंधन, इकाई	सोलन
7. ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई	सोलन
8. ग्राम, तहसील, जिला	टोप की बेर, जिला सोलन

एफआईएस प्राणु मलऊन से प्राणु सैंज ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई, रामपुर

1. सिंचाई उप परियोजना का नाम	प्राणु मलऊन से प्राणु सैंज
2. अनुमानित लागत (रु.)	28,29,100/-
3. जी.सी.ए. (हेक्टेयर)	18.58
4. सी.सी.ए. (हेक्टेयर)	13.79
5. लाभार्थी किसान परिवारों की संख्या	22
6. जिला परियोजना प्रबंधन, इकाई	सोलन
7. ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई	रामपुर
8. ग्राम, तहसील, जिला	कीर्ति, शिमला

एफआईएस किंगल ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई, रामपुर

1. सिंचाई उप परियोजना का नाम	किंगल
2. अनुमानित लागत (रु.)	41,98,400/-
3. जी.सी.ए. (हेक्टेयर)	17.84
4. सी.सी.ए. (हेक्टेयर)	12.32
5. लाभार्थी किसान परिवारों की संख्या	32
6. जिला परियोजना प्रबंधन, इकाई	सोलन
7. ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई	रामपुर
8. ग्राम, तहसील, जिला	ज़ार, शिमला

एफआईएस पन्धारा चोकन ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई, नाहन

1. सिंचाई उप परियोजना का नाम	पन्धारा चोकन
2. अनुमानित लागत (रु.)	34.04,500/-
3. जी.सी.ए. (हेक्टेयर)	12.24
4. सी.सी.ए. (हेक्टेयर)	10.41
5. लाभार्थी किसान परिवारों की संख्या	36
6. जिला परियोजना प्रबंधन, इकाई	सोलन
7. ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई	नाहन
8. ग्राम, तहसील, जिला	कोठिया जजर, सिरमौर

एफआईएस भलजा नाला टू वासनी ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई, नाहन

1. सिंचाई उप परियोजना का नाम	पन्धारा चोकन
2. अनुमानित लागत (रु.)	24,06,986/-
3. जी.सी.ए. (हेक्टेयर)	14.79
4. सी.सी.ए. (हेक्टेयर)	8.29
5. लाभार्थी किसान परिवारों की संख्या	46
6. जिला परियोजना प्रबंधन, इकाई	सोलन
7. ब्लॉक परियोजना प्रबंधन, इकाई	नाहन
8. ग्राम, तहसील, जिला	वासनी, सिरमौर

सिंचाई योजना गुम्मा का निर्माण कार्य ठेकेदार को सौंपा

मण्डी। हिमाचल प्रदेश में चल रहे फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना, जायका-2, मंडी द्वारा दिनांक 18.03.2025 को जल बहाव सिंचाई योजना गुम्मा को निर्माण हेतु ठेकेदार दिवांकर सिंह कंवर को कृषक विकास संघ गुम्मा के सदस्यों की उपस्थिति में सौंपी गई। ठेकेदार ने योजना निर्माण अनुसूची कृषक विकास संघ गुम्मा की उपस्थिति में खण्ड परियोजना प्रबंधन इकाई मंडी को सौंपी तथा ठेकेदार ने खण्ड परियोजना प्रबंधक मंडी, डॉ. राजेश कुमार, निर्माण अभियंता तथा कृषक विकास संघ को आश्वस्त किया कि योजना का निर्माण कार्य दी गई अनुसची के अनुसार तय समय पर पूर्ण गुणवता के साथ पूरा किया जाएगा। इस उपलक्ष में कृषक विकास संघ के प्रधान मुरारी लाल, सचिव हरी सिंह व अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस सिंचाई योजना के अंर्तगत 43.62 है0 क्षेत्रफल सिंचित होगा। इस योजना से निर्माण से लगभग 107 लाभांवित परिवारों को फायदा होगा। इस योजना से किसानों को कई लाभ होंगे जैसे कि किसानों के खेतों तक नियमित रूप से सिंचाई सुनिश्चित करवाना, कृषि प्रसार और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना, मूल्य श्रृंखला प्रबंधन इत्यादि।

नंदोह-गाही सिंचाई उप परियोजना किसानों को समर्पित

सनवारा जाबली क्षेत्र के 5 गांवों के किसानों की 40 हेक्टेयर जमीन होगी सिंचित

सोलन। सोलन जिला की दो पंचायत जाबली और सनवारा के पांच गांव में कृषि गतिविधियों को विकसित करने के लिए सिंचाई योजना को लाभार्थी किसानों को समर्पित किया है। जायका के तहत बनी इस सिंचाई उप परियोजना पर लगभग 1.15 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।

इसके बनने से 90 किसान परिवारों को लाभ हुआ और करीब 40 हेक्टेयर जमीन इससे सिंचित होगी।

दिनांक 3 मार्च, 2025 को इस सिंचाई योजना को लाभार्थी किसानों को समर्पित किया गया। मौके पर खंड परियोजना प्रबंधक, डॉ. अरुण कुमार शर्मा और परियोजना से डॉ. तनबी सूद, दिपांशी, कनिष्ठ अभियंता अंकित ठाकुर व बीडीसी सदस्य मैना देवी, प्रधान कल्पना गर्ग, विनय, तुलाराम, जयदत्त, ताराचंद, लाभार्थी किसानों सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

इस मौके पर सिंचाई कूहल की रख-रखाव की जिम्मेदारी कृषक विकास संघ नंदोह-गाही को सौंपी गई है।

सिंचाई परियोजना के बनने से क्षेत्र के पांच गांवों नंदोह, गाहीव, सैंज, धारड़ी और कार्ली की लगभग 40 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

सिंचाई योजना के तहत 4500 मीटर लम्बी कूहल, पांच टैंक, पाईप और बांध का निर्माण किया गया है। इस योजना में उपरोक्त खर्च के अलावा लगभग 2.13 लाख के कृषि उपकरण लाभार्थी किसानों को उपलब्ध करवाए गए हैं।

खरार उठाऊ सिंचाई योजना निर्माण लिए ठेकेदार को सौंपी

खरार उप परियोजना में नुक्कड़ नाटक से किसानों को किया जागरूक

ज्वाली, 18 मार्च 2025। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना-2 के तहत उठाऊ सिंचाई उप परियोजना, खरार में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसमें किसानों को फसल विविधीकरण और अन्य योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने विशेष उत्साह दिखाया और बढ़-चढ़कर भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य किसानों को कृषि में नए नवाचारों और जल प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों से अवगत कराना था, जिससे वे अपनी उपज को बढ़ाकर आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें।

सिंचाई योजना के विकास में महत्वपूर्ण कदम

कार्यक्रम के दौरान केवीए द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को साइट सौंपने की प्रक्रिया भी पूरी की गई। इसके साथ ही, केवीए सदस्यों, कॉन्ट्रैक्टर, विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सीसीए का संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिससे परियोजना की प्रगति का आंकलन किया गया।

50 हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित, 76 किसान होंगे लाभान्वित

नलकूप सिंचाई योजना के माध्यम से लगभग 91 लाख रुपये का व्यय किया जायेगा, जिससे 40 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इस परियोजना से क्षेत्र के 76 किसान सीधे लाभान्वित होंगे, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता और आय में वृद्धि होगी। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना-2 के तहत इस तरह के प्रयास किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं।

पंज्याला गांव में सिंचाई योजना 'पंज कूहल' का निर्माण शुरू

152 किसानों को मिलेगा लाभ, 52.92 हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित

धर्मशाला। बैजनाथ की पंज्याला पंचायत में बहाव सिंचाई योजना के तहत 'पंज कूहल' का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। जायका परियोजना के अंतर्गत संचालित इस महत्वपूर्ण सिंचाई योजना से क्षेत्र के लगभग 152 किसान परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 52.92 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे किसानों को वर्ष भर पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

खेती में होगा नवाचार, कैश क्रॉप को मिलेगा बढ़ावा

'पंज कूहल' सिंचाई परियोजना के प्रभाव से किसान पारंपरिक फसल उत्पादन के साथ-साथ कैश क्रॉप (नकदी फसलों) की ओर भी रुख कर सकेंगे। यह योजना स्थानीय किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और कृषि उत्पादन में विविधता लाने में सहायक होगी।

इस पहल से किसानों को खेती के लिए वर्ष भर पानी उपलब्ध रहेगा, जिससे वे अपनी फसलों की पैदावार को बढ़ा सकेंगे और अपनी आमदनी में सुधार कर सकेंगे। परियोजना के सफल क्रियान्वयन से न केवल जल संसाधनों का समुचित प्रबंधन होगा, बल्कि क्षेत्र में सतत् कृषि विकास को भी नई दिशा मिलेगी।

तंगरोटी के किसानों को मिलेगी 37 लाख रुपए की लागत से बनी कूहल

कांगड़ा। कांगड़ा जिले के तंगरोटी गांव के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। अब किसानों को सिंचाई के लिए पानी की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। कृषि विभाग के जायका परियोजना के तहत तंगरोटी गांव में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 37 लाख रुपये की लागत से पतलून बहाव सिंचाई योजना को मंजूरी मिल गई है। इस महत्वपूर्ण परियोजना का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा और इसे आठ माह के भीतर पूरा करने डुका लक्ष्य रखा गया है।

इस सिंचाई परियोजना के तहत बनने वाली कूहल से लगभग 14 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित किया जा सकेगा। इससे गांव के 48 किसान परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। पानी की निरंतर उपलब्धता से किसानों की कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और उनकी आय भी बढ़ेगी। सिंचाई सुविधा मिलने से किसानों को अब मौसम की अनिश्चितताओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे वे अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी

कृषि क्षेत्र में सिंचाई एक महत्वपूर्ण कारक है, जो उत्पादकता को सीधे प्रभावित करता है। इस परियोजना से किसानों को न केवल पानी की पर्याप्त आपूर्ति मिलेगी, बल्कि वे फसलों की विविधता को भी बढ़ा सकेंगे। किसानों के लिए यह योजना एक वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि यह उनकी कृषि लागत को कम करने और उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होगी।

सरकार की पहल से किसानों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर

राज्य सरकार और कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही इस तरह की योजनाएं किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इस योजना से तंगरोटी गांव के किसानों को एक स्थायी और प्रभावी सिंचाई प्रणाली उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें सूखे या जल की कमी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तंगरोटी गांव के किसानों ने इस परियोजना को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने सरकार और कृषि विभाग का आभार प्रकट करते हुए उम्मीद जताई है कि यह परियोजना जल्द से जल्द पूरी होगी। किसानों का कहना है कि इस योजना के लागू होने से उनकी खेती सुचारू रूप से संचालित होगी और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।

हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 (जायका ओडीए) के स्वामित्व में परियोजना निदेशक द्वारा परियोजना भवन, कृषि परिसर, हमीरपुर-177001 से संपादित, प्रकाशित एवं मुद्रित।
फोन: 01972-223059. ई-मेल : iechpjicaagriculture9@gmail.com